स्मार्ट टॉयलेट के नाम पर फिर शुरू होगी लूट

- पांच साल भी नहीं चल सके दो करोड़ रुपये की लागत वाले स्मार्ट शौचालय
- स्टेनलेस स्टील के शौचालयों में लग गया जंग अब दोबारा लूट कमाई की तैयारी

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) भ्रष्टाचार और लूट कमाई के लिए घोषित की गई मोदी की स्मार्ट सिटी योजना के अंत में एक बार फिर स्मार्ट टॉयलेट के नाम पर लाखों की लूट होगी। दो करोड़ रुपये लागत से वर्ष 2018 में लगाए गए स्मार्ट टॉयलेट तो तीन साल में ही बर्बाद हो गए। अधिकारी ठेकेदार पर कार्रवाई करने के बजाय फिर से इस योजना पर करोड़ों रुपये लूटने-लुटवाने की तैयारी कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही स्मार्ट सिटी का सब्ज़बाग़ जनता को दिखाया था। औद्योगिक नगरी भी स्मार्ट सिटी चुनी गई थी। इसके विकास के लिए प्रतिवर्ष सौ करोड़ रुपये खर्च किए जाने थे। चार साल तक कागजों और योजनाओं पर दौड़ती रही स्मार्ट सिटी 2017 तक कहीं नजर नहीं आई। तब स्मार्ट टॉयलेट का ढिंढोरा पीटा गया। शहर में दो करोड़ की लागत से दस स्मार्ट टायलेट लगाए गए। तब इन बाजार से चार गुना अधिक कीमत यानी बीस लाख रुपये का एक टॉयलेट खरीदे जाने और इनकी गुणवत्ता खराब होने का मुद्दा भी उठा था। इस सबके बीच आठ फरवरी 2018 को केंद्रीय मंत्री किशनपाल गूजर और बड़खल विधायक सीमा त्रिखा ने सेक्टर 21 में स्मार्ट टायलेट का समारोहपूर्वक उद्घाटन किया। तब इन नेताओं और स्मार्ट सिटी अधिकारियों ने स्टेनलेस स्टील के बने इन स्मार्ट टायलेट के दशकों तक खराब नहीं होने, इनमें ऑटोमेटिक सेनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, ऑटो क्लीनिंग सिस्टम, पैनिक बटन आदि लगा होने का दावा किया गया था। उदघाटन के एक महीने के भीतर ही यह स्मार्ट टॉयलेट बेकार साबित होने लगे थे। दो साल के भीतर इन कथित स्टेनलेस स्टील टॉयलटों में जंग लगने लगा और इनकी बॉडी गल कर इस्तेमाल योग्य भी नहीं रह गई। जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदार या करीबी होने के कारण ठेकेदार ने टॉयलेट लगाने के बाद कभी पलट कर इनकी सुधि नहीं ली, न ही भ्रष्ट अधिकारियों ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की।

अब प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट टॉयलेट लगाने की योजना तैयार कर रही है। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद से नगर निगम के कार्यकारी अभियंता नितिन कादियान और करनाल के नगर निगमायुक्त अभिषेक मीणा अहमदाबाद गुजरात में लगाए गए स्मार्ट टायलेट का अध्ययन करने जाएंगे। लौटने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगे। इसके बाद शहर में स्मार्ट टायलेट लगाए जाएंगे।

भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के कारण दो करोड़ के स्मार्ट टायलेटों की बर्बादी देखने के बाद भी यदि मुख्यमंत्री आंख के अंधे और गांठ के पूरे व्यक्ति की तरह इस प्रोजेक्ट पर अपनी मुहर लगाते हैं तो मान लिया जाना चाहिए कि वह भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस का केवल राग अलापते हैं। नए स्मार्ट टायलेट का प्रोजेक्ट पास करने से पहले उन्हें अधिकारियों से स्मार्ट सिटी के स्मार्ट टायलेटों की रिपोर्ट तलब करनी चाहिए। बिना इस्तेमाल केवल दो साल में ही बेकार होने के लिए उन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने बीस लाख रुपये में एक टॉयलेट लगवाया था, स्मार्ट सिटी परियोजना के पांच साल पूरे नहीं कर पाने के लिए अधिकारियों और ठेकेदारों से इस नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए, लेकिन दबंग नेताओं और चाटुकार व गुमराह करने वाले अधिकारियों से घिरे सीएम ऐसा कर पाएंगे, लगता नहीं है।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लबगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल-बस अड्डा होडल - 9991742421

वे ही भले रहे होते तो ये मदारी क्यों आये होते

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

वर्ष 2014 से पूर्व के कांग्रेसी शासनकाल में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार, घोटालों, महंगाई व बेरोजगारी से जनता इस कदर त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रही थी कि विकल्प के रूप में उसे वह मदारी मन को भा गया जो कहता था कि महंगाई से 100 दिन में राहत दिला देगा और प्रति वर्ष दो करोड़ नौकरियां उपलब्ध कराएगा। शायद, मदारी को यह सब पर्याप्त नहीं लगा तो घोषणा कर डाली कि विदेशों में छिपे काले धन को लाकर प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख डाल दिये जायेंगे। 'अच्छे दिन आयेंगे' का नारा देकर त्रस्त जनता को अपने मोहपाश में बांध कर सत्ता हथिया ली।

सत्तारूढ़ होते ही मदारी ने तुरंत अपना चोगा बदल लिया और असली रूप में आ गया। चुनाव पूर्व किये गये तमाम वायदों को जुमला बताते हुए एक के बाद एक अपने नये-नये एजेंडे रखने शुरू कर दिये। सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी के रूप में किया गया। सारे देश को बैंकों के बाहर कतारों में लगा दिया गया। सैंकड़ों लोग इन कतारों में खड़े-खड़े ही मर गये। लाखों लोग, खासकर दिहाड़ीदार मज़दूर व रेहड़ी-खोमचे वाले पूरी तरह से बेरोजगार हो गए।

मजे की बात तो यह रही कि मदारी ने जनता को इस कदर सम्मोहित कर रखा था कि इसके बावजूद भी वे उससे नाराज होते नजर नहीं आये क्योंकि उन्हें यह कह कर बरगलाया गया था कि इसके द्वारा वह देश का सारा काला धन समाप्त कर देगा। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके विपरीत, सारे का सारा काला धन सफेद हो गया, खासकर सत्तारूढ़ दल का जिसने सैंकड़ों करोड़ उन सहकारी बैंकों में जमा करा दिये थे जिनकी इतनी क्षमता ही नहीं थी।

चुनावी वायदों के विपरीत महंगाई को लगातार पूरी रफ्तार के साथ बढ़ाया गया तथा रोजगार बढ़ाने के बजाय तमाम सरकारी विभागों में भर्तियां लगभग बंद कर दी गईं। न केवल सारे बैंक बल्कि रिजर्व बैंक तक खाली करके अपने मित्र उद्योगपतियों के घर भर दिये। अपनी तमाम तरह की अय्याशियों के लिये भारी मात्रा में विदेशी कर्ज देश पर लाद दिये। इससे भी पेट नहीं भरा तो एक-एक करके देश की सम्पत्ति कौड़ियों के भाव अपने मित्रों को बेच डाली। इसके बावजूद बीते साढ़े नौ साल में एक भी कोई ऐसी चीज़ यानी कि कोई एम्स, आईआईटी अथवा कोई बड़ा संस्थान ये लोग नहीं बना पाये। बनाने के नाम पर केवल अपने आलीशान कार्यालय बनाये।

जनता के आक्रोश को दबाने के लिये पूरे मुख्यधारा के मीडिया को खरीद लिया गया। बिकाऊ मीडिया का केवल यही काम रह गया कि मात्र सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से मदारी की सुंदर-सुंदर तस्वीरें छापता रहे तथा उनके मतलब की तमाम झूठी खबरें फैलाता रहे। इसके साथ-साथ तमाम संवैधानिक संस्थानों-चुनाव आयोग, कैग, सीबीआई, ईडी आदि के अलावा न्यायपालिका तक को अपने कब्जे में कर लिया ताकि विरोध के उठने वाले प्रत्येक स्वर को कुचल दिया जाए, जो बोले वही जेल के अंदर। जाहिर है कि लोकतांत्रिक कही जा सकने वाली कोई बात छोड़ी नहीं गई।

जनता का असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिये मदारी गिरोह ने अपना पूरा जोर साम्प्रदायिक जहर बोने में लगा रखा है। तमाम बिकाऊ टीवी चैनलों पर असल मुद्दों के बजाय हिन्दू-मुस्लिम जैसे साम्प्रदायिक मुद्दों पर जहरीली एवं भड़काऊ बहसें कराई जाती हैं। त्रस्त जनता को धर्म की अफीम चटा कर यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि उनका असल मुद्दा हिन्दू-धर्म की रक्षा करना रह गया है न कि महंगाई व बेरोजगारी से निजात पाना, न कि शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे मुद्दों की बात करना।

इतने लम्बे समय तक मदारी गिरोह का पाखंड एवं फ़रेब ढोने के बाद अब जनता की आंख कुछ खुलने लगी है। इस गिरोह के प्रति जो अंधभक्ति सन् 2013-14 में विकसित हो गई थी वह अब ध्वस्त होती नजर आ रही है। दूसरी ओर राजनीतिक स्तर पर इन्हें चुनौती देने के लिये लगभग तमाम विपक्षी दलों ने भी इंडिया नामक गठबंधन खड़ा कर लिया है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 2019 के चुनावों में मदारी गिरोह को मात्र 37 प्रतिशत वोट मिले थे। जाहिर है कि शेष 63 प्रतिशत मतदाता मदारी गिरोह के विरुद्ध खड़े थे। लेकिन इन मतों के विभाजन के चलते मदारी गिरोह कामयाब रहा। इस बार यानी 2023-24 चुनावों के लिए विपक्षी गठबंधन ने तय किया है कि वे अपने वोट को बंटने से रोकेंगे। इसके लिये मदारी गिरोह के सामने केवल एक संयुक्त प्रत्याशी खड़ा करेंगे। सत्ता की लालसा प्रत्येक दल व उसके नेता को रहती ही है, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब उनके सामने मजबूरी यह है कि यदि 2024 में भी मदारी गिरोह फिर से सत्तारूढ़ हो गया तो देश में फ़िर कभी चुनाव नहीं होंगे। न कोई न्यायपालिका बचेगी और न कोई संविधान बचेगा। विरोध करने वाला कोई भी नेता जेल से बाहर नज़र नहीं आयेगा। इसी मजबूरी के चलते गठबंधन के घटकों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को स्थगित करके चुनाव में उतरना होगा।

इसके बाद बड़ा सवाल ये आता है कि यदि गठबंधन मदारी गिरोह से सत्ता छीन लेने में कामयाब होता है तो वह करेगा क्या? सत्तारूढ़ होने के बाद वह जनता को क्या राहत देगा? क्या वह मदारी गिरोह द्वारा उठाये गये तमाम जनविरोधी कानूनों को रद्द करके 2014 से पहले वाली स्थिति में ला पाएंगे? पेट्रोलियम पर बार-बार बढ़ाये गये उत्पाद शुल्क को पहले वाली स्थिति में ला पाएंगे? मदारी ने अपने जिन मित्रों पर देश का खजाना लुटाया है तथा देश की सम्पत्ति उनके हवाले की है क्या उसे वापस ला पायेंगे? शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बजट में भारी कटौतियां करके, इन्हें जिस कदर जनसाधारण की पहुंच से बाहर कर दिया है, उसे वापस कर पायेंगे? शिक्षण संस्थानों सहित तमाम सरकारी विभागों में जिस क्रूरता एवं बेशर्मी के साथ नफरती जहर बोया गया है, क्या उसे आने वाली सरकार उसी क्रूरता से कुचल पायेगी?

अब तक के ज्ञात राजनीतिक इतिहास के मुताबिक कोई भी आने वाली सरकार कभी भी पिछली सरकार द्वारा थोपे गये टैक्सों एवं कटौतियों से निजात नहीं दिलाती। हर आने वाली सरकार सदैव उससे आगे की ओर चलती है। सरकारी उपक्रमों को बेचने का काम, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बजट में कटौतियां करने का काम तथा बैंकों का धन उद्योगपतियों पर लुटाने का काम तो पुरानी सभी सरकारें करती रही हैं। संवैधानिक संस्थानों का दुरूपयोग भी पुरानी सरकारें करती रही हैं। अंतर केवल इतना ही है कि मदारी गिरोह ने ये सारे काम छाती ठोंक कर पूरी बेशर्मी के साथ तथा तीव्र गति के साथ कर डाले।